गन्ना किसानों के लिए बनाएं ठोस योजना

पीएम ने ली बैठक : किसानों की बदहाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता

- चीनी निर्यात और एथनॉल उत्पादन बढ़ाने पर विचार
- अंतिम फैसला लेने को अगले पखवाड़े फिर बुलाई बैठक

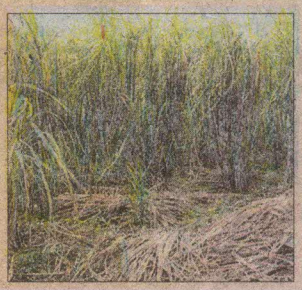

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घाटे से जूझ रहे चीनी उद्योग और बकाये से आजिज गन्ना किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में संबंधित सभी मंत्रालयों को कारगर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को हुई इस बैठक में किसानों की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों के हित में तत्काल कारगर कदम उठाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए चीनी निर्यात, एथनॉल उत्पादन बढ़ाने समेत अन्य उपायों पर योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अगले एक पखवाड़े के बाद यह बैठक दोबारा बुलाई जाएगी, जिसमें कुछ ठोस फैसला लिए जाने की संभावना है। बैठक में कृषि, खाद्य, वाणिज्यि, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

देश में चीनी के भारी स्टॉक और अगले पेराई सीजन में गन्ने की बंपर पैदावार को देखते हुए घरेलू बाजार में चीनी लागत मूल्य से कम भाव पर बिक रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें नीचे होने के चलते निर्यात की संभावनाएं नगण्य हैं। नगदी के अभाव में मिलें किसानों के गन्ने का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों का सात हजार करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है। इसी तरह महाराष्ट्र व कर्नाटक के किसानों का बकाया तीन-तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। शनिवार की उच्चस्तरीय बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत इन सभी मंत्रालयों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के उच्चाधिकारियों ने भी पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। बैठक में केंद्र सरकार के चीनी उद्योग को अब तक दी गई हजारों करोड़ की रियायतों की समीक्षा की गई। वाणिज्य मंत्रालय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के निर्यात की संभावनाएं तलाशने को कहा गया। कृषि मंत्रालय को गन्ने के खेती का वास्तविक रकबा और चीनी पैदावार का वास्तविक अनुमान लगाने का निर्देश दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को बढ़ाने की संभावना पर विचार करने को कहा गया।

उप्र में मिलों की हालत ज्यादा खराब

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की हालत इस कदर खराब है कि ज्यादातर गन्ना किसानों का भुगतान अभी अटका पड़ा है। कृषि राज्यमंत्री बालियान ने बताया कि मवाना और मोदी चीनी उद्योग समूह की मिलों ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इन मिलों ने मात्र पांच से दस फीसदी गन्ने का भुगतान किया है। दूसरी ओर बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर समूह ने अपनी कई मिलों में पेराई न करने का नोटिस दे रखा है, जबकि उन क्षेत्रों के किसानों ने भारी रकबे में गन्ने की खेती कर रखी है।

शांति आंदोलन मंगलवार को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीनी उद्योग की बदहाली के बावजूद सरकारी उदासीनता को लेकर देश भर के गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक मंगलवार को दिल्ली में शांति आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चीनी के लिए 'उचित मूल्य' घोषित करने की मांग भी की है। आंदोलन के संयोजक ओम प्रकाश धानुका कहते हैं कि यह पहला मौका है जब गन्ना उत्पादक और चीनी मिल मालिक से लेकर चीनी व्यापारी, मजदूर, तकनीशियन व मशीन आपूर्तिकर्ता एकजुट हैं। 'ऑल इंडिया गन्ना उत्पादक संगठन' और 'ऑल इंडिया चीनी उत्पादक संगठन' ने साझा तौर पर इस समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए 4 अगस्त को शांति आंदोलन का आयोजन किया है। अपनी मांग के समर्थन में चीनी उत्पादन से जुड़े लोग इस दिन बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेंगे। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर भी अपनी मांगों से अवगत करवाया है। इनका कहना है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चीनी के लिए 'उचित मूल्य' घोषित करे। साथ ही सभी चीनी मिलो के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे आयोग की ओर से घोषित अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर इसे नहीं बेचें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की घटी कीमत की वजह से भी ये बेहद परेशान हैं।

Dainik Jagaran
2/8/15